ए.एल. बहरी, जे. के समक्ष

बिजेंदर सिंह.-याचिकाकर्ता.

बनाम

रामबीर सिंह और अन्य,-प्रतिवादी

सिविल पुनरीक्षण संख्या 2737 का 1990

18 जनवरी 1991

सिविल प्रक्रिया संहिता (V का 1908)—आदेश 9, नियम 7 और 13—एकतरफा कार्यवाही को रद्द करना–उचित सेवा प्रभावित नहीं हुई–आदेश 9 नियम 13 के तहत समन की सेवा में अनियमितता और आदेश 9, नियम 7 के संबंध में गैर-सेवा–भेदभाव उल्लेखित।

निर्धारित किया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 में निहित सिद्धांत कि समन की सेवा में अनियमितता के कारण एकतरफा फैसला रद्द नहीं किया जाना चाहिए, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 7 के तहत दायर आवेदनों पर लागू नहीं होता है। अनियमित सेवा या सेवा में दोष का मामला सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 7 के संबंध में गैर-सेवा के मामले के बराबर होगा। सूट में समन की गैर-सेवा के कारण नियत तारीख पर उपस्थित न होने के कारण एकतरफा कार्यवाही को रद्द करने का एक अच्छा कारण होगा। ऐसे प्रतिवादी को उसके उपस्थित होने पर और अच्छा कारण दिखाने पर मुकदमे का विरोध करने का अधिकार होगा, जिसमें वह अपनी लिखित बयान दायर कर सकता है और उसके पास उपलब्ध सभी तर्क दे सकता है। (पैरा 8 & 9)

धारा 115 सीपीसी के तहत संशोधन याचिका श्री एन. एल. प्रूथी, वरिष्ठ उप न्यायाधीश, सोनीपत की अदालत के 24 अगस्त, 1990 के आदेश के खिलाफ, जिसमें 8 जून, 1988 के एकतरफा आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया था।

दावा: प्रतिवादी संख्या 4 बिजेंदर सिंह के खिलाफ एकतरफा आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन। याचिका में दावा: निचली अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए।

एस. सी. कपूर, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए।

आई. डी. सिंगला, अधिवक्ता, प्रतिवादी के लिए।

निर्णय

ए.एल. बहरी, जे.

1) यह संशोधन याचिका 24 अगस्त, 1990 को वरिष्ठ उप न्यायाधीश, सोनीपत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें 8 जून, 1988 के एकतरफा आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था, जिसके द्वारा बिजेंदर सिंह, मुकदमे में से एक प्रतिवादी, के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई थी।

2) बिजेंदर सिंह और अन्य के खिलाफ एक प्री-एम्प्शन का मुकदमा दायर किया गया था। बिजेंदर सिंह का पता गाँव जुआन, तहसील और जिला सोनीपत दिया गया था। रिपोर्ट यह थी कि वह गाँव में नहीं रह रहा था। बिजेंदर सिंह के दिल्ली के पते पर भेजे गए एक और सेट के समन पर, इनकार की रिपोर्ट थी। इसके बाद, गाँव में ड्रम की बीट से प्रचार द्वारा सेवा की गई और बिजेंदर सिंह के 8 जून, 1988 को अनुपस्थिति के लिए उसे एकतरफा कार्यवाही के खिलाफ आदेश दिया गया था।

3) एकतरफा आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन में, बिजेंदर सिंह ने कहा था कि वह दिल्ली का निवासी है जहाँ वह सेवा में था और उसने कभी किसी समन का इनकार नहीं किया था। उसे उचित रूप से सेवा नहीं दी गई थी। मुकदमे के लंबित होने का पता चलने पर उसने आवेदन दायर किया। इस आवेदन का विरोध किया गया और निम्नलिखित मुद्दे तय किए गए: –

   (i) क्या 13 मई, 1988 का आदेश (वास्तव में 8 जून, 1988) रद्द किए जाने के लिए योग्य है जैसा कि आरोपित किया गया है? ओपीए

   (ii) राहत।

4) दोनों पक्षों के साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद, चुनौती योग्य आदेश पारित किया गया।

5) यह तथ्य कि वादीगण ने बिजेंदर सिंह के नाम पर दिल्ली के पते के साथ समन लिया था, यह दर्शाता है कि संबंधित समय पर वह गाँव में नहीं रह रहा था, बल्कि दिल्ली में था। इस प्रकार, गाँव में ड्रम की बीट से प्रचार द्वारा उसकी प्रतिस्थापन सेवा के लिए अदालत से प्राप्त बाद के आदेश तथ्यों के खिलाफ थे। ऐसे प्रचार को किसी भी तरह से बिजेंदर सिंह पर उचित सेवा के रूप में नहीं माना जा सकता है।

6) AW-3 बिजेंदर सिंह ने कहा कि पिछले आठ वर्षों से वह दिल्ली में रह रहे हैं। पहले वह छात्र थे और उसके बाद वह सेवा में हैं। बेशक, क्रॉस-परीक्षण के दौरान उनसे पूछा गया था कि उन्होंने अपने निवास के संबंध में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं लाए थे और उन्होंने जवाब दिया था कि वह वही प्रस्तुत करेंगे लेकिन उन्होंने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, चूंकि वादीगण का भी मामला था कि बिजेंदर सिंह दिल्ली में रह रहे थे, इसलिए उनके नाम पर समन प्राप्त किए गए थे, अब यह महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने अपना राशन-कार्ड या अन्य दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए जो वहां उनके निवास को इंगित करते हैं। समन प्रस्तुत करने पर इनकार की रिपोर्ट तब साबित नहीं हुई थी जब पक्षों को तय मुद्दों पर साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इनकार की तथ्यता विवादित थी और वादीगण पर बोझ था कि वे प्रक्रिया सर्वर को प्रस्तुत करें जिसने बिजेंदर सिंह को समन प्रस्तुत किया था और उसने

उसे अस्वीकार कर दिया था। ऐसे साक्ष्य की अनुपस्थिति में, उसकी रिपोर्ट पर से रिकॉर्ड होने के कारण उसे साक्ष्य के रूप में माना नहीं जा सकता था कि वास्तव में उसने समन के स्वीकार करने का इनकार किया था। इस स्थिति में, यह कोई अन्य निष्कर्ष नहीं था कि बिजेंदर सिंह को मुकदमे में उचित रूप से सेवा नहीं दी गई थी।

7) प्रतिवादियों की ओर से यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता अन्य प्रतिवादियों का भाई होने के नाते, उसे मुकदमे के लंबित होने की जानकारी का आभास किया जा सकता है। किसी दिए गए परिस्थिति सेट में, ऐसी धारणा उठाई जा सकती है लेकिन वर्तमान मामले में मैं नहीं पाता कि रिकॉर्ड पर ऐसी धारणा उठाने के लिए कोई अन्य परिस्थितियाँ लाई गई हैं, खासकर जब अन्य प्रतिवादी दिल्ली में नहीं रहते हैं। प्रश्नित आदेश में, निचली अदालत ने राजस्व अधिकारियों के सामने बिजेंदर सिंह की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर प्रस्तुत R1 पर भरोसा किया। हालांकि, इस तथ्य को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता है और श्री आर. एस. हुडा, अधिवक्ता (RW2) का यह साक्ष्य कि उन्होंने बिजेंदर सिंह के लिए आवेदन तैयार किया था। बेशक, बिजेंदर सिंह मूल रूप से गाँव जुआन का निवासी है जहाँ उसके और उसके भाइयों की संपत्ति है और यदि भाइयों के बीच भूमि संबंधित विभाजन प्रक्रिया में गाँव का पता दिया गया था, तो इसका वर्तमान आवेदन के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता है।

8) आदेश IX सी.पी.सी. के नियम 13 में निहित सिद्धांत कि समन की सेवा में अनियमितता के कारण एकतरफा फैसला रद्द नहीं किया जाना चाहिए, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 7 के तहत दायर आवेदनों पर लागू नहीं होता है। आदेश 9 के नियम 7 का पाठ इस प्रकार है: –

> "जहां अदालत ने मुकदमे की सुनवाई एकतरफा स्थगित की है, और प्रतिवादी, ऐसी सुनवाई पर या उससे पहले उपस्थित होता है और अपनी पिछली अनुपस्थिति के लिए अच्छा कारण बताता है, वह, अदालत के निर्देशों के अनुसार खर्च या अन्यथा के संबंध में, मुकदमे के उत्तर में सुना जा सकता है जैसे कि वह उसके उपस्थित होने के लिए निर्धारित दिन उपस्थित हुआ था।"

9) अनियमित सेवा या सेवा में दोष का मामला सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 7 के संबंध में गैर-सेवा के मामले के बराबर होगा। सूट में समन की गैर-सेवा के कारण नियत तारीख पर अनुपस्थिति के लिए एकतरफा कार्यवाही को रद्द करने का एक अच्छा मामला होगा। ऐसे प्रतिवादी को उसके उपस्थित होने पर और अच्छा कारण दिखाने पर मुकदमे का विरोध करने का अधिकार होगा, जिसमें वह अपनी लिखित बयान दायर कर सकता है और उसके पास उपलब्ध सभी तर्क दे सकता है।

10) उपर्युक्त कारणों से, यह संशोधन याचिका खर्च के बिना स्वीकार की जाती है। प्रश्नित आदेश रद्द किया जाता है और याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही को रद्द करने के लिए स्वीकार किया जाता है। पक्षों को उनके

वकीलों के माध्यम से 11 फरवरी, 1991 को निचली अदालत में मुकदमे की आगे की कार्यवाही के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आयुष
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार
हिसार, हरियाणा